बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 160

एफपीआई को बढ़ावा

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए नियामकीय एवं अनुपालन मानक को शिथिल कर दिया है। बाजार नियामक ने यह आश्वस्ति भी दी है कि वह पार्टिसिपेटरी नोट जारी करने के मानकों को भी तार्किक बनाएगा ताकि एफपीआई के लिए इन उपायों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की सेवा करना आसान हो सके। इन उपायों की मदद से एफपीआई की नकारात्मक धारणा कम करने और भारतीय शेयर बाजार में उनका दोबारा प्रवेश सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। बजट के बाद से ही वे इस क्षेत्र से भारी बिकवाली कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार नियामक ने कर्ज में राहत की घोषणा भी की है। सूचीबद्ध कंपनियों में वित्तीय अनुषंगियों के साथ पुनर्खरीद के लिए आवश्यक इक्विटी अनुपात शिथिल किया गया है। इतना ही नहीं सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और उनके ग्राहकों के लिए नियमन सख्त किए हैं। उसने एक स्पष्ट समझौते की मांग की है जिसके जरिये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मौजूदा या भविष्य की उधारी की पूरी जानकारी देने को कहा गया है। उसने एक सूचना प्रणाली का प्रस्ताव भी रखा है ताकि भेदिया कारोबार के मामलों में समय से प्रमाण जुटाए जा सकें। नए एफपीआई मानक व्यापक तौर पर एचआर खान समिति की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हैं। कई चीजों को सरल भी बनाया गया है। 57 प्रासंगिक परिपत्रों को एक परिपत्र में समेट दिया गया है। अब सेबी एफपीआई को तीन के बजाय दो श्रेणियों में बांटेगा। यह वर्गीकरण, ग्राहक को जानने संबंधी मानक तथा अन्य अनुपालन इस बात पर निर्भर करेंगे कि उक्त संस्था का उसके घरेलू बाजार में किस प्रकार नियमन हो रहा है। वह पुरानी व्यवस्था खत्म की जाएगी जहां एफपीआई को केवल तभी व्यापक प्रभाव वाली श्रेणी दी जाती थी जबकि उसमें 20 या अधिक निवेशक होते थे। भारतीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा शुरू किए गए बाहरी फंडों को भी देश में निवेश के लिए एफपीआई के रूप में पंजीयन की छूट दी जाएगी। अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों को भी एफपीआई के रूप में पंजीयन की अनुमति दी जाएगी, भले ही वे बैंक ऑफ इंटरनैशनल सेटलमेंट्स के सदस्य न हों। वर्ष 2017 से पी-नोट जारी करने पर प्रतिबंध था। ऐसा केवल हेजिंग के उद्देश्य से किया गया था। यह प्रतिबंध हटाया जाएगा और इन्हें प्राथमिकता देने वालों के लिए चीजें आसान होंगी। हालांकि ये सहजीकरण एफपीआई के पंजीयन और व्यापार को काफी सहज बनाते हैं लेकिन अगर धारणा में सुधार लाना है तो वित्त मंत्रालय को भी दखल देना होगा। चुनिंदा एफपीआई मसलन पेंशन फंड आदि को केवल न्यास के रूप में परिचालन की अनुमति है क्योंकि उनके यहां नियमन ऐसे ही हैं। ताजा बजट में एक तय स्तर से अधिक आय पर अधिभार ऐसे सभी एफपीआई को प्रभावित करती है। यही कारण है कि बजट की घोषणा से अब तक एफपीआई 3 अरब डॉलर मूल्य के शेयर बेच चुके हैं। अधिभार खत्म करने से बिकवाली का दबाव कम होगा हालांकि कई निवेशक मंदी को लेकर भी निराश हैं। पुनर्खरीद मानकों में बदलाव से उन कंपनियों को लाभ होगा जो एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों की मालिक हैं। इन वित्तीय अनुषंगियों का अपना ऋण: इक्विटी अनुपात 6:1 तक हो सकता है। पुराने मानकों के तहत पुनर्खरीद के बाद समेकित कंपनी का अनुपात 2:1 या इससे कम होना था। संशोधन के बाद यह शिथिल हुआ है और अलहदा कंपनी का ऋण और इक्विटी अनुपात 2:1 या उससे कम होना चाहिए। समेकित ऋण इक्विटी अनुपात भी 2:1 या उससे कम होगा। हालांकि समेकित अनुपात का आकलन वित्तीय अनुषंगी को बाहर रखकर किया जाएगा। ये बदलाव एफपीआई और पुनर्खरीद की राह तक रहे कॉर्पोरेट की राह आसान बनाएंगे। यह वित्त मंत्रालय पर निर्भर करता है कि वह कर के मोर्चे पर इसका अनुकरण करे।

बिनय सिन्हा

ब्रेक्सिट के पैमाने पर ब्रिटेन का लोकतंत्र

ब्रेक्सिट की वजह से ब्रिटेन को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर मतभेदों को समुचित जगह देकर उसने लोकतंत्र की जीवंत तस्वीर पेश की है। बता रहे हैं पार्थसारथि शोम

ब्रिटेन न केवल यूरोप के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों एवं अफसरशाहों बल्कि अटलांटिक-पार के राजनीतिक एवं आर्थिक साझेदारों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भी झुंझलाहट का सबब रहा है। यूरोपीय संघ से अलगाव (ब्रेक्सिट) और इसके बहुआयामी प्रभावों का खाका तैयार करने में आपाधापी नजर आती है। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी समेत सभी दलों के नेता ब्रेक्सिट पर अलग विचार पेश करते रहे हैं जो कई बार आधिकारिक रुख के उलट भी होता है। पेंग्विन ने ब्रेक्सिट को लेकर बनाए गए कार्टूनों का एक दिलचस्प संग्रह भी प्रकाशित किया है। व्हाट्सऐप तो ब्रेक्सिट से जुड़े व्यंग्यों का स्थायी स्रोत रहा है।

यूरोपीय संघ से अलग होने का सम्मानजनक तरीका तलाशने में ब्रिटेन की अक्षमता किसी अंतरिम या दीर्घावधि व्यवस्था में निहित जटिलताओं का अंदाजा लगा पाने में उसकी अदूरदर्शिता भी बयां करती है। पूर्व प्रधानमंत्री टरीसा मे के बारे में यह सोच रही कि उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्सिट समझौते पर सहमति जताने के पहले अपने मंत्रिमंडल और संसद में इस मुद्दे पर समुचित परामर्श नहीं किया था।

जब टरीसा ने ब्रेक्सिट पैकेज को मंत्रिमंडल और संसद के समक्ष रखा तो काफी विरोधाभासी सुर सुनने को मिले। उनके कार्यालय से पैकेज का नया रूप जारी किए जाने के बाद भी उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उनके विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने इन इस्तीफों की अगुआई की थी। कंजर्वेटिव नेतृत्व की होड़ में पिछली बार जॉनसन को टरीसा से पिछड़ना पड़ा था लेकिन बदले हुए हालात में उसी पार्टी के एक लाख कार्यकर्ताओं ने जॉनसन को अपना नेता चुन लिया है। यहां ध्यान देना जरूरी है कि बहुत छोटे मतदाता समूह ने जॉनसन को नया प्रधानमंत्री चुना है। यह यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जून 2016 में कराए गए जनमत संग्रह की याद दिलाता है जिसमें 40 फीसदी से भी कम मतदाताओं ने अलग होने का समर्थन किया था।

हालांकि ब्रेक्सिट प्रक्रिया पर गौर करें तो घटनाक्रम से सीखने के लिए एक दिलचस्प नजारा सामने आता है। टरीसा की तरफ से कई पैकेज पेश करना, संसद का उन्हें तत्काल नकार देना, हार मानने से उनका इनकार और फिर नया पैकेज लेकर आना, संसद एवं उनके सहयोगियों का किसी पर भी राजी न होना और आखिर में चुनिंदा समर्थकों का साथ छोड़कर चले जाना। यह पूरा चक्र एक बुनियादी आस्था पर टिके रहने और लोकतंत्र की निडर परंपरा को बयां करता है जिसे दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में एक मिसाल माना जाना चाहिए।

ब्रिटेन के बहुत कम दोस्तों या सहयोगियों ने ही इसे समझा है। कुछ हद तक इस स्थिति को प्रधानमंत्री के रूप में टरीसा के कार्यकाल पर नजर डालकर समझा जा सकता है। ब्रेक्सिट पर टरीसा की तरफ से पेश पहले पैकेज को संसद में नकारे जाने के साथ ही उनकी विदाई का माहौल बनने लगा। प्रेक्षकों ने भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत- खुलकर अपनी बात कहने की आजादी की ब्रिटिश लोकतंत्र में मौजूदगी पर अधिक ध्यान नहीं दिया।

इस आजादी के ही चलते कंजर्वेटिव एवं लेबर पार्टी के नेताओं के अलावा मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी ब्रेक्सिट पैकेज पर प्रधानमंत्री टरीसा से चुपचाप सहमति जताने के बजाय खुलकर अपनी राय रखने, असहमति जताने, इस्तीफा देने और अपनी राय बदलने जैसे काम कर सके। सांसदों ने दलगत दायरों से बाहर निकलते हुए किसी मुद्दे पर अलग समूह भी बनाए। इन अंतर्दलीय समूहों ने ब्रेक्सिट पर चार वैकल्पिक पैकेज भी पेश किए थे। कंजर्वेटिव सांसद सर ओलिवर लेटविन ने इन वैकल्पिक सुझावों को समाहित करने के लिए रचनात्मक पहल की थी लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए।

टरीसा यूरोप से कोई सौदा किए बगैर भी बाहर आ सकती थीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे उन्होंने कहा था कि एक बुरे सौदे से बेहतर है कोई सौदा न होना। उन्होंने हल निकालने की कोशिश बार-बार की लेकिन लोकतंत्र के पहिये उन पर भारी पड़ गए। आखिरकार 24 जुलाई को टरीसा मे ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ने का ऐलान कर दिया और जॉनसन ने उनकी जगह ले ली। नए प्रधानमंत्री ने यह साफ करने में थोड़ी भी देर नहीं की कि यूरोपीय संघ अगर उनकी मांग नहीं मानता है तो वह 30 अक्टूबर को यूरोप से नाता तोड़ने में कोई गुरेज नहीं करेंगे।

सवाल है कि ब्रिटेन यहां से किधर जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू से ही ब्रेक्सिट का समर्थन किया था और टरीसा के प्रधानमंत्री रहते समय भी जॉनसन को बेहतर विकल्प बता दिया था। क्या यह मान लिया जाए कि ब्रेक्सिट हो जाने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच बढ़िया सौदे आसानी से हो जाएंगे? लेकिन अमेरिका के मौजूदा कारोबारी रुख को देखें तो ऐसा अनिश्चित ही लग रहा है।

ब्रिटेन के समक्ष अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मामलों एवं घरेलू आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन की मुश्किल चुनौती है। घरेलू स्तर पर ब्रिटेन का विश्व युद्ध-पश्चात ढांचा एटली योजना 1949 पर बना था। इस योजना के तहत स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप के जरिये आय वितरण की हालत सुधारने का उद्देश्य रखा गया था। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर जूलियन लीग्रांड जैसे अर्थशास्त्रियों ने वर्ष 1980 आने तक एटली योजना की उपलब्धियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। वर्ष 2017-18 तक हालात और भी बिगड़ चुके थे। इन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

इन सुविधाओं में नैशनल हेल्थ सर्विस भी शामिल है जिसमें एक सामान्य डॉक्टर से भी परामर्श लेने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। अस्पतालों के आपातकालीन विभाग भरे पड़े हैं। ट्रेनों की हालत खस्ता हो चुकी है। शिक्षा का स्तर भी पहले से गिरा है। सार्वजनिक आवासन को निजी हाथों में दिया जा चुका है और निजी डेवलपरों को सब्सिडी वाले मकान मुहैया कराने के लिए सख्त सरकारी मानकों का पालन करना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि बिना सब्सिडी वाले आवासीय प्रोजेक्ट के दाम आसमान पर जा पहुंचे हैं। इस तरह रियायती आवासीय प्रोजेक्ट का बोझ अब बिना सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट को उठाना पड़ रहा है।

अंत में, क्या ब्रेक्सिट इस कवायद के लायक है? इतिहास की शुरुआत इलिजाबेथ प्रथम से होती है जिनकी छोटी नौसेना ने स्पेन की ताकतवर सेना को हराकर ब्रिटिश अवाम में अपनी महत्ता का अहसास जगाया था। सदियों से यूरोप के लोग शाही परिवार समेत समूचे ब्रिटेन में आते रहे लेकिन ब्रिटेन ने अलग पहचान वाले द्वीप की पहचान बनाए रखी। यूरोप का हिस्सा बनने के बाद यूरोपीय अफसरशाही मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र का निर्धारण करती रही लेकिन ब्रिटेन ने खुद को आत्मसात नहीं किए जाने पर अंत में संयम खो दिया। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन के लोगों ने ब्रेक्सिट के पक्ष में मतदान कर दिया।

बहरहाल इसकी ऊंची कीमत देनी पड़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन का यूरोप के साथ मुक्त व्यापार बंद हो जाएगा। ब्रिटेन को दुनिया भर में लंबी एवं थकाऊ व्यापार वार्ताएं शुरू करनी होंगी। उसे अपनी उन्नत तकनीकों को बढ़िया दाम पर बेचने में काफी चतुराई दिखानी होगी। उसे विनिर्माण में तेजी लाने के लिए खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा और युवाओं को उत्पादक रोजगार में शामिल करना होगा। एक मुश्किल सफर उसका इंतजार कर रहा है।

हालांकि एक पेच बाकी है। टरीसा मे की विदाई से पहले लंदन में ब्रेक्सिट के खिलाफ लाखों की मुहिम को नजरअंदाज किया गया जबकि ब्रेक्सिट के पक्ष में आवाज ने जोर पकड़ा। वह लोकतंत्र की एक अकेली आवाज है जिसने सवाल खड़े किए।

क्वांटम कंप्यूटिंग से लाभ अपार लेकिन करना होगा इंतजार

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

क्वांटम कंप्यूटिंग ने बहुत से वादे किए और काफी संसाधनों का उपयोग किया लेकिन इससे बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग संबंधी शोध कार्यों में निवेश को तर्कसंगत कहा जा सकता है। सैद्धांतिक रूप में क्वांटम कंप्यूटर किसी भी सामान्य कंप्यूटर के मुकाबले काफी तेज गति से काम कर सकता है जिससे अनसुलझे लगने वाले सवालों का हल खोजा जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में होने वाले कार्यों ने कई वैज्ञानिक घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है।

इंजीनियरिंग क्षेत्र की समस्याएं काफी बड़ी और जटिल होती हैं। सुपरपोजिशन और इंटैंगलमेंट (एक जैसी क्वांटम अवस्था वाले अलग अणु) क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र की दो मुख्य विधाएं हैं। क्वांटम स्तर पर कोई अणु एक ही समय में दो अलग-अलग अवस्था में रह सकता है, अथवा उसके दो अवस्थाओं में रहने की संभावना है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। अणु की ये अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अर्थात एक अणु की स्थिति में बदलाव करने पर उसके जुड़वा अणु में तत्काल परिवर्तन दिखाई देगा, भले ही उनके बीच काफी दूरी हो। इन दोनों बुनियादी विशेषताओं के कारण क्वांटम कंप्यूटर तेज गति से काम करते हैं। हमारे मोबाइल या सामान्य कंप्यूटर ऑन/ऑफ वाले 'लॉजिक गेट' सर्किट के साथ बाइनरी सिद्धांतों पर काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में सुपरपोजिशन विशेषता के चलते एक ही समय में किसी अणु को स्विच ऑन या ऑफ, दोनों स्थितियों में रखा जा सकता है। इसलिए किसी बिट में एक समय में केवल एक परिणाम को सहेजा जा सकता है लेकिन क्वांटम बिट (क्यूबिट) में एक ही समय पर दोनों परिणामों को संग्रहीत किया जा सकता है।

दो क्यूबिट का एक सर्किट किसी भी क्षण सुपरपोजिशन की चार संभावित अवस्थाओं में हो सकता है जबकि दो बिट का साधारण सर्किट इनमें से केवल एक अवस्था में होगा। इसलिए अधिक क्यूबिट वाला प्रोसेसर किसी सामान्य सर्किट के मुकाबले तुलनात्मक रूप में कई गुना तेजी से जानकारी संसाधित कर सकता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के अनुसार, 'पेनिसिलिन की आणविक संरचना को देखें तो इसकी स्थायी अवस्था में 41 परमाणु होते हैं जिसके लिए 1,086 बिट के साधारण कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। व्यावहारिक तौर पर इस तरह की मशीन बनाना नामुमकिन है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर के लिए 286 क्यूबिट वाले प्रोसेसर की ही जरूरत होगी।'

जब भी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित गणना के अंतिम परिणाम को मापा जाता है तो वह सुपरपोजिशन से इतर सामान्य अवस्था में मिलता है। किसी क्यूबिट सर्किट को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत लगती है क्योंकि छोटी सी गड़बड़ी से अणुओं की संबद्धता टूट सकती है। साथ ही, क्वांटम कंप्यूटर बहुत अधिक डेटा उपलब्ध कराते हैं जिसके लिए बड़े स्तर पर त्रुटि सुधार की आवश्यकता है।

फिलहाल क्यूबिट चिप को निर्वात में लगभग शून्य तापमान पर सहेजा जाता है जो केवल नियंत्रित प्रयोगशालाओं में ही संभव है। इन्हें किसी भी तरह की हलचल से दूर रखा जाता है क्योंकि व्यक्ति के चलने की आवाज से भी अणुओं में संबद्धता टूट सकती है।

कंप्यूटर वैज्ञानिक लॉजिकल क्यूबिट को क्वांटम क्षेत्र की 'मुद्रा' के तौर पर देखते हैं। लॉजिकल क्यूबिट का उपयोग एक समय में दो स्थितियों के लिए किया जा सकता है। इसमें कई भौतिक क्यूबिट या अतिचालकता वाले सर्किट हो सकते हैं जो किसी परमाणु की अवस्था की संरचना का निर्माण करते हैं। एक तथ्य यह भी है कि किसी साधारण कंप्यूटर के सर्किट में लॉजिकल क्यूबिट सर्किट का उपयोग करके क्वांटम मशीन की नकल बनाई जा सकती है। क्वांटम एल्गोरिद्म का परीक्षण करने के लिए कई बार ऐसा किया गया है।

इस क्षेत्र में लगातार बेहतरी के प्रयास हो रहे हैं। फिलहाल विश्व का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर गूगल का ब्रिस्टलेकॉन है जिसमें 72 फिजिकल क्यूबिट प्रोसेसर लगा है। चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी ने 18 क्यूबिट वाला कंप्यूटर बनाया है। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी (सिडनी) की शोध टीम ने सिलिकन में फॉस्फोरस परमाणु को अंत:स्थापित कर दो क्यूबिट वाले लॉजिक गेट की प्रसंस्करण क्षमता और बढ़ा दी है।

क्वांटम क्षेत्र में वर्चस्व हासिल करने के लिए सामान्य कंप्यूटर को पछाड़ने के वास्ते न्यूनतम 50 लॉजिकल क्यूबिट प्रोसेसिंग क्षमता की जरूरत होगी। हालांकि बड़े अणुओं के अध्ययन या कृत्रिम मेधा (एआई) एल्गोरिद्म के लिए लगभग 1,000 लॉजिकल क्यूबिट क्षमता की आवश्यकता होगी। आरएसए 2048 एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड के लिए 4,000 क्यूबिट क्षमता वाली मशीन की जरूरत होगी।

एक समस्या त्रुटि से जुड़ी है। अधिक क्यूबिट वाला सर्किट गॉड पार्टिकल की खोज के लिए बनाए गए लार्ज हैड्रॉन कोलाइटर से भी अधिक डेटा उत्पन्न करेगा। इस डेटा में बहुत सी त्रुटियां होंगी जिनमें सुधार करना होगा। क्वांटम एल्गोरिद्म को लिखना और क्वांटम मशीन पर बड़ी मात्रा में डेटा भेजना भी काफी जटिल काम है। बीसीजी का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से उत्पादकता में बेहतरी के चलते सालाना 450 अरब डॉलर से अधिक का लाभ होगा। उसने कहा, 'हालांकि अगले पांच वर्षों के लिए यह गति थोड़ी धीमी रहेगी। हमारा मानना है कि वर्ष 2024 तक यह कीमत 2-5 अरब डॉलर हो जाएगी। तकनीक के उन्नत होने पर इसमें क्रमिक बढ़ोतरी होगी।'

क्वांटम कंप्यूटिंग की सहायता से दवाइयों के निर्माण, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन अनुमान और एनक्रिप्शन पद्धति में महत्त्वपूर्ण बदलाव होंगे। शोध के सहारे नए तत्त्वों के बारे में जानकारी मिलेगी लेकिन इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

कानाफूसी

बिकता नहीं विमान

मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लंबे समय से सात सीट वाले अपने पुराने विमान को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। जनवरी में राज्य सरकार ने सुपर किंग एयर बी-200 विमान को बेचने के लिए वैश्विक निविदा जारी की थी। सरकार ने इसका आधार मूल्य 11.1 करोड़ रुपये से अधिक रखा था। उस समय सरकार को एक भी खरीदार नहीं मिला। बाद में सरकार ने दो और प्रयास किए लेकिन उसे इस विमान को बेचने में कामयाबी नहीं मिली। यह विमान 18 वर्ष पुराना है और राज्य सरकार को महत्त्वपूर्ण अतिथियों के लिए अपेक्षाकृत नए विमान किराये पर लेने पड़ते हैं। इससे पहले सत्तासीन रही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इस विमान को बेचने का प्रयास किया था लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिल सकी थी। उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थी और उसने भाजपा के प्रयास की आलोचना करते हुए कहा था कि विमान को बेचना राज्य के मूल्यवान संसाधनों की बरबादी के समान होगा।

आपका पक्ष

आदिवासी संस्कृति और विकास

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पिछले दिनों आदिवासी समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। इसका कारण वहां एक पहाड़ पर खुदाई शुरू करना था जिसका आदिवासी विरोध कर रहे थे। आदिवासियों का मानना है कि उक्त पहाड़ पर उनके ग्राम देवता विराजमान हैं जिसकी ईष्ट देव के रूप में पूजा की जाती है। बैलाडीला क्षेत्र की 13 नंबर की इस पहाड़ पर बहुत ही उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क पाया गया है। यह लड़ाई भावनात्मक बनाम आर्थिक लाभ की प्रतीत होती है। भारत को विकास की राह पर चलना है लेकिन अगर विकास जनजाति संस्कृति को क्षति पहुंचाते हुए आगे बढ़ता है तो न ही संस्कृति रहेगी और न ही विकास। बहरहाल, सरकार और स्थानीय लोगों को इसका समाधान खोजना होगा। ऐसे कई उदाहरण स्थानीय और वैश्विक रूप में मौजूद हैं जहां विकास भी अपनी राह पर चल पड़ा तथा संस्कृति व प्रकृति अक्षुण्ण रही। विकास और प्रकृति टकराते हैं तब बलिदान हमेशा प्रकृति और संस्कृति को ही क्यों देनी पड़े। हमारे अपने जनजातीय लोगों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समृद्ध विरासत के धनी ये लोग विभिन्न कला संस्कृति व रीति-रिवाजों को संजोये हुए हैं। इन सभी का संरक्षण आवश्यक है वरना विकास के नाम पर हस्तक्षेप करने से ये लुप्त होते चले जाएंगे। अंदरूनी इलाकों, जंगलों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लगाए जाने वाले उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार की प्राथमिकता देकर विकास और संस्कृति के बीच तालमेल बिठाया जा सकता है। उद्योग लाभांश का हिस्सा तथा खनिज रॉयल्टी के धन का उपयोग स्थानीय लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर खर्च करके संघर्ष को कम किया जा सकता है। उद्योग अगर स्थानीय संसाधनों का उपयोग करे तो लाभ का पर्याप्त हिस्सा वहां के विकास कार्य में खर्च हो। आदिवासी युवागृहों को विकृत किए बिना सुविधायुक्त आधुनिक हॉस्टलों में क्यों नहीं बदला जा सकता है। नवाचार और नवोन्मेष के विभिन्न पहलू हमारी संस्कृति पर भी बराबर लागू होते हैं। बौद्धिक आलस्य और वैचारिक संकीर्णता को त्यागकर, जनजातियों को हाशिये में न धकेल कर उन्हें मुख्यधारा में लाना होगा। तभी विकास भी न्यायसंगत होगा और सांस्कृतिक संरक्षण भी।

जीतेंद्र साहू, शहडोल

बैलाडीह पहाड़ पर खनन के विरोध में आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया था

नियम कानून का पालन करें माननीय

सोलहवीं लोकसभा 25 मई को भंग कर दी गई। इसके बावजूद अबतक 200 पूर्व सांसदों द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किए जाने की खबर आई है। उक्त सांसदों को वर्ष 2014 में सरकारी आवासआवंटित किए गए थे। देश में नियम कानून हर नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। अगर माननीय ही नियम कानून नहीं मानेंगे तो आम आदमी उनका हवाला देकर नियमों को मानने से कतराते नजर आएंगे। खबर के अनुसार उक्त सांसदों ने बंगले खाली नहीं करने के संबंध में कुछ कहा नहीं है लेकिन वे तय समय में सरकारी बंगले खाली कर एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई पूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास अदालत के हस्तक्षेप के बाद खाली कराया गया था। ऐसी घटना से समाज में उचित संदेश नहीं जाता है। अत: माननीय को स्वयं पहले नियम कानून का पालन करना चाहिए।

उदित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।